

शर्यहाश दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-11 7 जून, 2015 पृष्ठों की संख्या 4 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

मूल्य : 1 रुपये

फासीवाद पर समाजवाद की विजय की 70वीं वर्षगाँठ विजय के सूत्रधार महान स्टालिन की याद में

ठीक 70 वर्ष पहले - 9 मई, 1945 का यह ऐतिहासिक दिन था—जब बहादुर और साहसी लाल फौज ने क्रूर जर्मन फासीवादी फौजों को करारी शिकस्त देते हुए बर्लिन पर कब्जा कर लिया था और जर्मन संसद भवन राइस्टाग पर लाल झण्डा फहराया था जो बुराई की ताकतों पर मानवजाति की जीत का प्रतीक था और जर्मनी के युद्ध-विरोधी जनवादपसंद लोगों सहित जिन्होंने फासीवादी गेस्टेपो और एसएस वाहिनी के हाथों घोर यातनाएं सही थीं, पूरी दुनिया ने बेबाकी से स्वीकार किया था कि ये सर्वहारा के महान नेता, मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन के योग्य उत्तराधिकारी, दृढ़ इच्छाशक्ति और जीवत से भरपूर तथा मुक्ति के लिए मानवजाति के संघर्ष के इतिहास में एक उच्च चरित्र के धनी स्टालिन ही थे जो मानवजाति के अति क्रूर शत्रु पर मानवजाति की इस युगांतकारी जीत के सूत्रधार और मानव सभ्यता के रक्षक थे। उनके नेतृत्व में बहादुर सोवियत जनता, लाल फौज और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रतिक्रिया की ताकतों पर यह जीत हासिल की थी।

सोवियत समाजवाद को अस्थिर करने का बुर्जुआ षड्यन्त्र

1917 में सोवियत समाजवादी क्रान्ति ने एक नए युग का सूत्रपात किया और मार्क्सवादी दर्शन की सटीकता और इतिहास के मार्क्सवादी विश्लेषण की अचूकता को सिद्ध किया था। पूरी दुनिया ने मानव द्वारा मानव के शोषण से मुक्त एक नए समाज के आगमन और मानवजाति के आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक चौराहा विकास के संवर्धन को लक्ष्य किया। इसने दुनिया भर के मजदूर वर्ग को मार्क्सवाद-लेनिनवाद से लैस होने और अपने अपने देशों में क्रान्तिकारी संघर्षों को गठित करने के लिए प्रेरित किया। इसने उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों में मुक्तिकामी लोगों को साम्राज्यवादी-सामंती ताकतों के चंगुल से अपने देशों को मुक्त कराने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। सोवियत क्रान्ति ने पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति से भयाक्रांत प्रतिक्रियावादी विश्व साम्राज्यवाद-पूँजीवाद की रोढ़ में सिहरन भी पैदा कर दी थी। इसीलिए, साम्राज्यवादी-पूँजीवादी ताकतों ने सोवियत समाजवाद को अस्थिर करने और ध्वस्त करने के लिए तमाम तरह के षड्यन्त्र रचने शुरू कर दिए थे। सोवियत यूनियन की चौराहा सामरिक घेराबंदी के लिए कदम उठाए गए थे। उस देश में अंदरूनी गड़बड़ी और षड्यन्त्र रचने के लिए उत्तेजना भड़काने वाले तत्वों को रोपित किया गया। सत्ता से उखाड़े गए रूसी पूँजीपतियों को छिपे तौर से हर तरह की मदद दी गई ताकि प्रतिक्रान्ति की जा सके। महान लेनिन के कीर्तिशाली नेतृत्व के तहत नवजात सोवियत यूनियन इन तमाम पूँजीवादी षड्यंत्रों के खिलाफ डट कर खड़ा रहा, समाजवाद को मजबूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तथा जीवन के हर क्षेत्र में पूँजीवाद पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। तमाम उठापटक और बाधाओं को पार करते हुए अनुभवहीन समाजवाद को बचाने और प्रतिक्रिया की ताकतों की तमाम तिकड़मबाजियों को परास्त करने का भार 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद लेनिन के अति भरोसेमंद शिष्य व सहयोगी स्टालिन के कंधों पर भार आ गया। ये स्टालिन ही थे जिन्होंने लेनिनवाद को आधार प्रदान किया और दिखाया कि लेनिनवाद ही साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रान्ति के युग का मार्क्सवाद है जबकि साथ ही साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में शानदार विकास कराते हुए समाजवाद को यथाशीघ्र मजबूती प्रदान करने के लिए सोवियत यूनियन के तमाम लोगों को प्रेरित किया। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आदर्शों, नई उच्च सर्वहारा नैतिकता और संस्कृति से

लैस और सामाजिक दायित्वबोध तथा उद्देश्यपरायणता की अभूतपूर्व भावना को प्रतिबिम्बित करते हुए लोगों ने स्टालिन के आह्वान का तहेदिल से प्रत्युत्तर दिया। मात्र दो दशकों के अल्प समय में ही सोवियत यूनियन औद्योगिकीकरण और फसल उत्पादन में स्थापित साम्राज्यवादी ताकतों से भी आगे निकल गया था। लोगों का जीवन स्तर जबर्दस्त ऊपर उठा, कीमते बहेद षट गई, बेरोजगारी, भिखमंगी, वैश्यावृत्ति और पूँजीवादी समाज की ऐसी ही अन्य व्याधियाँ अतीत की बात हो गई। सोवियत पार्टी के अन्दर निन्दकों और वर्ग-द्रोहियों के समाजवाद को ध्वस्त करने के मनहूस षड्यंत्र का भी स्टालिन ने सख्ती से मुकाबला किया और तमाम तरह के विरूपण और विकृतीकरण से मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सारतत्व को बचाने के लिए निरन्तर जोरदार वैचारिक संघर्ष चलाया।

जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा सोवियत समाजवाद मात्र दो दशक का था

लेकिन जब समाजवाद सोवियत यूनियन में जड़ें जमा रहा था और विश्व साम्यवादी आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था तब जर्मनी और इटली में फासीवाद के उदय के चलते दुनिया खतरे में पड़ गई तथा एक और विनाशकारी विश्व युद्ध के काले बादल मण्डराने लगे। लेनिन ने बहुत पहले दिखाया था कि बाजार को हड़पने और नियंत्रण को लेकर साम्राज्यवादी युद्ध पैदा करते हैं। उन्होंने व्याख्या दी कि प्रथम विश्वयुद्ध युद्धरत दोनों पक्षों की तरफ से साम्राज्यवादी (यानी हड़प लेने, लील देने, लूटमार करने का) युद्ध था; यह दुनिया के बंटवारे, उपनिवेशों के बंटवारे और पुनः बंटवारे, वित्तीय पूँजी के “प्रभाव क्षेत्रों”, के विस्तार इत्यादि के लिए युद्ध था। दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मनी और इटली (जापान बाद में शामिल हुआ) फासीवादी थुरी का उद्देश्य भी यही था—बंदूक की नोक पर विश्व बाजार हड़पना ताकि इसे अपने प्रभुत्व में रखा जा सके। जातीय श्रेष्ठता और राष्ट्रीय युद्धप्रियता के सिद्धांत को उकसा कर और प्रगतिशील नारे उठाते हुए हिटलर बहुसंख्यक जर्मन लोगों को अपने पीछे लामबंद कर सका था और तमाम दूसरे देशों पर सामरिक आक्रमण करने और उन्हें अपने अधीन करने के लिए एक शक्तिशाली युद्ध मशीन तैयार करने में जुट गया था। हिटलर की योजना पहले ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम जैसी और अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों को कुचलना था। उसकी समझदारी थी कि क्योंकि क्रान्ति-पूर्व रूस अति पिछड़ा था इसलिए नवजात समाजवादी सोवियत यूनियन उसकी सामरिक शक्ति के आगे ठहर नहीं सकता था। इसलिए सोवियत यूनियन को बाद में मात्र उंगली के एक इशारे से हड़पा जा सकता। पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों—अमेरिका-ब्रिटेन-फ्रांस ने भी चाहा था कि हिटलर सोवियत यूनियन पर आक्रमण करे, प्रथम समाजवादी देश और विश्व की प्रथम मजदूर वर्गीय राजसत्ता को तबाह कर दे। महान कम्युनिस्ट नेता स्टालिन हिटलर की इस परोक्ष रणनीति को समझ गए थे और पश्चिमी “डैमोक्रेटिक” शासकों के इरादे को भी भांप गये थे। असल में, जब राष्ट्रीय समाजवाद का नारा देकर हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था, स्टालिन समझ गए थे कि हिटलर के नारे का अंतर्निहित उद्देश्य और लक्ष्य क्या था और यह भी भांप लिया था कि दूसरा विश्व युद्ध होने वाला है। जनवरी 1934 में सी.पी.एस.यू. (बोल्शेविक) की 17वीं पार्टी कांग्रेस में रिपोर्ट के दौरान स्टालिन ने कहा था, “इसमें कोई हैरानी नहीं है (शेष पृष्ठ 2 पर)



21 मई को नेपाल के काठमांडू में यूसीपीएन (एम) के चेयरमैन डॉ. पुष्प कमल देहल ‘प्रचण्ड’ को भूकंप-पीड़ित राहत कोष का चेक सौंपते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य डॉ. कृष्ण चक्रवर्ती। उनके साथ खड़े हुए पार्टी के केन्द्रीय कमेटी सदस्य डॉ. सत्यवान

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के बुलावे पर दिल्ली में श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

नई दिल्ली : 11 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के बुलावे पर दिल्ली में 26 मई को मावलकर हाल में श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें बीएमएस, इंटक, एचएमएस, सीटू, एटक, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू, एआईयूटीयूसी, एलपीएफ, यूटीयूसी, सेवा और बैंक, बीमा, रक्षा, रेलवे, केन्द्रीय/राज्य कर्मचारियों व अन्य सेवा प्रतिष्ठानों की फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। केन्द्र व राज्य सरकारों की मजदूर-विरोधी, जनविरोधी और कारपोरेटपरस्त नीतियों, श्रम कानूनों में किये जा रहे मजदूर-विरोधी संशोधनों के खिलाफ और अपनी 12सूत्री मांगों के लिए आवाज बुलंद की गई। सम्मेलन के संचालन के लिए सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को लेकर बने अध्यक्षमंडल में एआईयूटीयूसी का प्रतिनिधित्व इसके सचिवमंडल सदस्य डॉ. सत्यवान ने किया। सम्मेलन को एआईयूटीयूसी के अध्यक्ष डॉ. कृष्ण चक्रवर्ती व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं ने सम्बोधित किया।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित घोषणापत्र में सभी ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों का आह्वान किया गया कि जमीनी स्तर

से अपनी एकता को व्यापक बनाते हुए आन्दोलन को मजबूत करें और सरकार की घोर मजदूर-विरोधी नीतियों का प्रतिरोध करने के लिए देशभर में संयुक्त आन्दोलन की तैयारी करें। सम्मेलन में सर्वसम्मति से कार्यक्रम लिया गया कि जून-जुलाई में राज्य, जिला व उद्योग स्तरीय संयुक्त सम्मेलन करें, अभियान चलायें और आम लोगों का सहयोग लें। 2 सितम्बर, 2015 को अखिल भारतीय आम हड़ताल करने का फैसला लिया गया।



दिल्ली में श्रमिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. कृष्ण चक्रवर्ती

फासीवाद पर समाजवाद की विजय की 70वीं वर्षगांठ ... (पृष्ठ 1 का शेष)

कि जब युद्धोन्मादी बुर्जुआ राजनीतियों के बीच फासीवाद एक बहुत ही फैशनेबुल चीज बन गया है। मैं सिर्फ आम तौर पर फासीवाद का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ बल्कि मुख्यतः जर्मन टाइप के फासीवाद की बात कर रहा हूँ, जिसे गलत ढंग से राष्ट्रीय समाजवाद कहा जा रहा है—गलत ढंग से क्योंकि अति सूक्ष्म पड़ताल भी इसमें समाजवाद का एक अणु मात्र भी उजागर करने में नाकाम रहेगी... सोशल डेमोक्रेसी जिसने फासीवाद के लिए रास्ता बनाया... इस बात का संकेत है कि पूँजीपति वर्ग संसदीय और बुर्जुआ डेमोक्रेसी के पुराने तरीके से अब और शासन करने में सक्षम नहीं है और परिणामस्वरूप अपनी गृह नीति में शासन के लिए आतंकवादी तरीके अपनाने को मजबूर है... और ...युद्ध की नीति का सहारा लेने पर बाध्य है।" तब उनकी चिन्ता और प्रमुख दायित्व दुनिया के मुक्तिकामी लोगों के सामने एकमात्र उम्मीद समाजवादी सोवियत यूनियन को बचाना था। दस्तावेज जिन्हें लगभग 70 सालों तक गुप्त रखा गया था और हाल ही में उजागर किए गए हैं, दर्शाते हैं कि सोवियत यूनियन ने ब्रिटेन और फ्रांस को नाजी-विरोधी गठजोड़ में लुभाने के प्रयास में एक शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स भेजने का प्रस्ताव दिया था। हिटलर को रोकने में मदद के लिए मिलिट्री फोर्स की पेशकश सोवियत ब्रिटिश और फ्रांसिसी अफसरों के साथ क्रममिलन बैठक में सोवियत सोवियत मिलिट्री डेलिगेशन द्वारा की गई थी, 1939 में युद्ध छिड़ने के ठीक दो सप्ताह पहले। लेकिन एक पश्चिमी गठजोड़ की स्टालिन की पेशकश को ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। (द टेलिग्राफ, यू.के., 18.10.2008) ऐसे हालात में स्टालिन ने चतुर कदम उठाये और 23 अगस्त, 1939 को हिटलर के साथ एक दूसरे पर हमला न करने का समझौता करके हर किसी को अचम्भे में डाल दिया था। हिटलर इस समझौते के लिए सहमत हो गया था। क्योंकि उसने सोचा कि यह उसे कमजोर पूर्वी यूरोपीय और बालकान राज्यों पर आसानी से कब्जा करने में सक्षम बना देगा और साथ ही साथ जल्द शुरू होने वाले द्वितीय विश्वयुद्ध में दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने से उसे बचा देगा। दूसरी तरफ स्टालिन ने निश्चित तौर से यह जानते हुए कि फासीवादी जर्मनी पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों पर विजय निश्चित हो जाने के बाद मौका मिलने ही तुरन्त सोवियत यूनियन पर झपट पड़ेगा, समय लेने में कामयाब हुए ताकि फासीवादी आक्रमण का सीधे-सीधे मुकाबला करने के लिए आवश्यक तैयारियों को कुछ मोहल्लत मिल सके और साथ ही साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और सामाजिक उत्थान में अब तक हासिल प्रगति की रक्षा के लिए कुछ सुरक्षा कदम उठाए जा सकें। इसी तरह, क्रोधित साम्राज्यवादी-पूँजीवादी ताकतों ने इस संधि को स्टालिन द्वारा हिटलर के साथ समझौते के रूप में पेश किया। आज भी प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ खेमा साथ ही साथ संशोधनवादी-वर्गद्रोही जो स्टालिन को तुच्छ साबित करना चाहते हैं और फासीवाद को हराने में उनकी भूमिका को स्वीकारने से इनकार करते हैं इसी संधि को विश्वासघाती काम की संज्ञा देते आ रहे हैं। लेकिन इतिहास ने सिद्ध कर दिया और साफ तौर से दिखा दिया कि जटिल स्थिति को संभालने में स्टालिन ने उस समय कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था जिसने मानवजाति को फासीवाद के शिकंजे से बचाने में मदद की थी।

पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की विश्वासघातक भूमिका

जैसी की अपेक्षा थी, संधि के दो साल के अन्दर, नाजी शासन ने यूरोप पर कब्जा करने के बाद सैनिकों और हथियारों को भारी संख्या में इकट्ठा करके 22 जून 1941 को सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया। एक बार पुनः पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की भूमिका के बारे में स्टालिन की दूरदर्शिता सही सिद्ध हुई जब नाजी हमले के मात्र दो दिन बाद अमेरिकन सिनेटर हैरी ट्रूमैन (जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने) ने टिप्पणी की थी, "यदि हम देखें कि जर्मनी युद्ध जीत रहा है तब हमें रूस की मदद करनी चाहिए और यदि हम देखें कि रूस जीत रहा है तो हमें हिटलर की मदद करनी चाहिए, ताकि दोनों पक्षों की तबाही हो।" तथाकथित मित्र शक्तियों का यह था असली चेहरा। अमेरिकन-ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने सपना संजोया था कि एक बार जर्मनी और सोवियत यूनियन दोनों तबाह हो जाएं तो वे पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लेंगे और अपने पूरे नियंत्रण में ले आएंगे। इस सम्बन्ध में यह बता देना प्रासंगिक है कि जब फासिस्ट फौज ने सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया था और अंधाधुंध नरसंहार और तबाही मचा रही थी, तब स्टालिन ने इन अमेरिकन-फ्रेंच-ब्रिटिश शासकों से पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलते हुए फ्रांस के माध्यम से जर्मनी पर आक्रमण करने का अनुरोध किया था। यदि ऐसा किया जाता तो हिटलर को पूर्वी युद्ध क्षेत्र से सैनिक हटाने और उन्हें पश्चिम में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ता जिससे सोवियत यूनियन पर आक्रमण की तीव्रता में कुछ हद तक कमी आ जाती। लेकिन पश्चिमी साम्राज्यवादी शासकों ने इसको अनसुना कर दिया।

कब उन्होंने दूसरा मोर्चा खोला? तब जब स्टालिन को उनकी मदद की और दरकार नहीं रही थी, क्योंकि सोवियत लाल फौज और जनता सफलतापूर्वक फासिस्ट जर्मन फौज को खदेड़ते हुए पूर्वी यूरोप में पीछा कर रही थी। तब 1944 में मित्र शक्तियों ने फ्रेंच समुद्री तट नॉरमैण्डो में अपनी सेनाएं उतारी और आक्रमण किया जिसका घृणित उद्देश्य था लाल फौज के पहुँचने से पहले बर्लिन पहुँचना। अतः सोवियत समाजवादी राज्य को दुर्जेय फासिस्ट सैनिक शक्ति के खिलाफ अकेले ही लड़ना पड़ा था। यहाँ इस बात का जिक्र कर देना भी जरूरी है कि घटनाक्रम के ऐसे एक मोड़ पर जब जर्मनी और जापान दोनों आत्मसमर्पण करने को थे तब अमेरिकन साम्राज्यवादी शासकों ने लाल फौज, बहादुर सोवियत जनता और महान स्टालिन को फासिस्ट धुरी को हराने के श्रेय से वंचित करने की खातिर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर 2 लाख से अधिक निरह जापानी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार खुद युद्ध जीतने का जयचोष करते हुए झूठा दावा पेश करने का प्रयास किया।

ब्रिटिश-फ्रांस-अमेरिका क्यों नाजी हमले को पीछे नहीं धकेल सके

लेकिन चालबाजियाँ और झांसेबाजियाँ सत्य को दबा नहीं सकती। क्यों ब्रिटेन और फ्रांस तब काफी सामरिक शक्ति रहते हुए भी फासिस्ट हमले को पहले ही पीछे नहीं धकेल सके? क्योंकि, जैसा कि हमने ऊपर बताया है दूसरा विश्व युद्ध और कुछ नहीं बल्कि विश्व पूँजीवादी बाजार को हड़पने के लिए एक साम्राज्यवादी युद्ध था। एक साम्राज्यवादी ताकत जर्मनी जिसे प्रथम विश्व युद्ध में एंग्लो-फ्रेंच साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों करारी शिकस्त मिली थी, अपना बाजार खो बैठा था और घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। वह उस बाजार को छीनना चाहता था जो अधिकतर ब्रिटिश-फ्रेंच-अमेरिकन

और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के बीच बँटा हुआ था। क्योंकि इसे युद्ध छेड़ कर ही हासिल किया जा सकता था अतः जर्मनी ने दूसरों पर युद्ध की घोषणा कर दी और इसी उद्देश्य के लिए उसे मुसोलिनी का इटली एक अन्य उदीयमान फासिस्ट ताकत के रूप में दोस्त मिल गया। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य साम्राज्यवादी देशों के लोग भी जानलेवा पूँजीवादी शोषण से पीड़ित थे जो विश्वव्यापी गहन आर्थिक मंदी के चलते और भी घनघोर हो गया था। उनके बीच असंतोष बढ़ रहा था और परिणामतः उनमें अपने शासकों के बारे में भ्रान्ति और अविश्वास पनप रहा था। इसलिए जब उनके देशों पर हमला हुआ तब शोषणकारी साम्राज्यवादी-पूँजीवादी शासक उनको वैचारिक और राजनैतिक तौर से प्रेरित नहीं कर सके कि वे आक्रामक शत्रु का मुकाबला करें। राष्ट्रीय एकता का आह्वान बेअसर रहा क्योंकि पूँजीवादी मालिकों और उत्पीड़ित मजदूर वर्ग जिनके हित एक दूसरे के विरोधी हैं, उनके बीच घनघोर संकट की वजह से द्रन्ध्र तीव्रतर हो रहा था। इसलिए ब्रिटेन-फ्रांस-अमेरिका और अन्यो को पूरी तरह अपनी भाड़े की फौज पर निर्भर रहना पड़ा। दूसरी तरफ हिटलर जानता था कि यूरेशियन देशों के अंदर बहुत से असंतुष्ट कबीले, घोर यहूदी-विरोधी नाजी-परस्त ग्रुप थे। जर्मन फासिस्टों को उन देशों में बहुत से भीतरघाती या देशद्रोही मिल गए जो कुछ फायदों या अन्य लाभों के एवज में अपने-अपने देशों के खिलाफ उनका साथ देने के इच्छुक थे। उन्होंने धूर्ततापूर्वक उन लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पश्चिमी देशों में गुरिल्ला युद्ध के रूप में जो भी थोड़ा बहुत जन प्रतिरोध हुआ वह ज्यादातर उन स्वयंसेवकों द्वारा किया गया जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और उन देशों में अपने अपने शासक पूँजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष संचालित कर रहे थे।

सोवियत प्रतिरोध समाजवादी विचारधारा और जन-शक्ति पर आधारित था

लेकिन सोवियत प्रतिरोध के साथ तस्वीर बिलकुल उलट थी। सोवियत समाजवाद शोषणमुक्त समाज था। साथ ही साथ आर्थिक शोषण के खात्मे के साथ सोवियत समाजवाद भाषागत, जातिगत, साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय द्वन्द्वों को दूर करने के अपने काम में बहुत दूर तक आगे बढ़ गया था। मार्क्सवाद-लेनिनवाद के महान आदर्श से लैस देश के तमाम लोग अपने खून के आखरी कतरों तक समाजवाद के निर्माण और उसको मजबूत करने में लगे थे। उक्रैन में जर्मन मूल के कबीले काफी संख्या में थे। लेकिन उनके बीच से हिटलर कोई देशद्रोही नहीं पा सका। जर्मन आक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में जब लाल फौज पीछे हट रही थी, तब भी बहु-भाषी, बहु-धर्मीय और अल्पसंख्यक लोगों वाले रूसी इलाकों के बाशिंदे जिन्हें नाजी सेनाओं द्वारा घोर यातनाएं दी जा रही थी उनमें से कोई भी बॉलशेविकों के खिलाफ नहीं गया। यहाँ तक कि जब जर्मन सेना आगे बढ़ी तो गुरिल्ला लड़ाकों (पार्टी नेतृत्व के तहत स्वयंसेवकों) ने जर्मन शस्त्रागार को उड़ा दिया, खाद्य सप्लाई को बन्द कर दिया, रेलवे और अन्य संचार माध्यमों को ध्वस्त कर दिया और सम्पत्त सूर काट दिया। उन्होंने ध्यान रखा कि फासिस्टों को गेहूँ जैसी आवश्यक खाद्य फसल, पीने का पानी आदि उपलब्ध न हों। जर्मन सेना मोर्चे पर लाल फौज और पिछवाड़े में गुरिल्लाओं के बीच फँस गई थी। लाल फौज कोई भाड़े की फौज नहीं थी बल्कि किसी भी कीमत पर समाजवाद को बचाने के लिए प्रतिबद्ध वैचारिक तौर से संगठित एक बटालियन थी। फासीवाद के खिलाफ बॉलशेविकों की लड़ाई अंधता के खिलाफ तर्कशीलता की, रेंजिमेंटेशनन के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, मानवजाति के हत्यारों के खिलाफ मानवजाति को एक लड़ाई थी। रूस में तब ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने अपने किसी सदस्य या नजदीकी को युद्ध में न खोया हो। जोय, लिजा, इवान, ओलेग, उलियाना, लुबोव या सरगेई जैसे गुरिल्ला योद्धाओं ने, जो रूस की बेहतरीन संतानें थीं—अपनी किशोर अवस्था में अपना जीवन बलिदान करके मिसाल पेश की थी। एक सोवियत किशोर जिसने सेबस्टोपोल में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी, उसने मौत से पहले कहा था, "मैं लेनिन के कॉमसोमोल का सदस्य हूँ।" स्टालिनग्राद के मोर्चे से लाल फौज के एक सैनिक ने स्टालिन को पत्र लिखा था: "आपके नाम पर हमारे पिताओं ने जा रिस्किन (स्टालिनग्राद का पूर्व नाम) को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया था, हम भी किसी भी कीमत पर स्टालिनग्राद को बचाएँगे।" स्टालिन की अपील का प्रत्युत्तर देते हुए न केवल लाल फौज बल्कि सभी नर-नारी, जवान और बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि हस्पतालों में भर्ती बीमार भी जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर लेनिनग्राद को बचाने की लड़ाई में शामिल हो गए थे। मध्यरात्रि में सोवियत चीफ कमाण्डर मार्शल जुकोव को स्टालिन ने टेलिफोन किया। फोन पर स्टालिन ने उनसे पूछा— "क्या आप लेनिनग्राद को बचाने में सक्षम होंगे?" जुकोव ने सकारात्मक उत्तर दिया। स्टालिन ने कहा— "मुझे एक कम्युनिस्ट की तरह जवाब दो।" हॉ वह उत्तर था बहादुर लाल फौज और लोगों द्वारा फासिस्ट फौजों को पीछे धकेल कर दिया गया। "लेनिनग्राद" यह नाम सोवियत लोगों, बुनियात के कम्युनिस्टों और मजदूर वर्ग के मन में कैसे कहा गया था। मध्यरात्रि में सोवियत फौजों की फासिस्ट आक्रमण जो बदहवास होकर अति अकल्पनीय बर्बरता के साथ समाजवाद को तबाह करने पर तुला था, उसके सामने अनुल्लंघनीय बाधा बन कर खड़े हो गए थे। विश्वव्यापी फासीवाद-विरोधी शक्ति के कर्णधार स्टालिन थे जो खुद एक महान क्रान्तिकारी संघर्ष की उपज थे जिनका जीवन क्रान्ति और लोगों के प्रति समर्पित था।

स्टालिन एक प्रमुख रणनीतिकार

समय की मांग को पूरा करते हुए स्टालिन ने युद्ध रणनीतियों में भी महारथ हासिल की थी। सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमाण्डर के रूप में चुने जाने के बाद जब बहुत ही अल्प समय में उन्होंने युद्ध की बारीकियों पर अपनी समग्र पकड़ को दर्शाया तो अनुभवी और जानकार रूसी जनरल भी भींचकर रह गए थे। चर्चिल और रूजवेल्ट, ब्रिटिश और अमेरिकी जनरल भी एक रणनीतिक मीटिंग के दौरान स्टालिन की युद्ध विज्ञान के बारे में असाधारण ज्ञान और पकड़ को देखकर हैरान हो गए थे। उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर उनकी युद्ध रणनीति को सूत्रबद्ध करने में भी मार्गदर्शन दिया था। स्टालिन ने बोधगम्य रूप से सिद्ध कर दिया था कि एक मार्क्सवादी क्रान्तिकारी नेता यदि जरूरत हो तो सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च पाण्डित्यता का धनी हो सकता है।

सभी स्टालिन को श्रद्धा करते थे

हिटलर के बदनामी अभियान का सूत्र पकड़ कर साम्राज्यवादियों-पूँजीवादियों ने जब स्टालिन को अमानवीय, बेरहम, बदले की भावना से प्रेरित और यहाँ तक की दैत्य ठहराने की कोशिश की थी, निश्चित ही भय की वजह से तब सच्चे राष्ट्रवादियों, मानवतावादियों, प्रख्यात बुद्धिजीवियों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों के साथ-साथ विभिन्न देशों के आम लोगों

फासीवाद पर समाजवाद की विजय की 70वीं वर्षगांठ ... (पृष्ठ 2 का शेष)

ने बॉलशेविकों का पक्ष लिया था और अलग ही मिट्टी के बने महान नेता के रूप में स्टालिन की सराहना की थी। महान मानवतावादी चिन्तनकार रोमां रोलां ने स्टालिन के बारे में लिखा था: “वे बुद्धिमान ... हमेशा चौकस, बेहिकक, स्पष्टवादी, सच्चे थे हालाँकि थोड़े से गंभीर थे। उनकी बुद्धिमत्ता कोई फैंसला लेने से पहले डगमगाती नहीं है। किसी बात को घुमा फिरा कर कहना उनकी आदत नहीं है। उनकी कूटनीति में धोखेबाजी का कोई स्थान नहीं है, न ही इसमें किसी प्रशस्ति या बड़बोलेपन का कोई स्थान है।... मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी प्रकृति का पूरा ढांचा तीव्र तर्कसंगतता, असीम धैर्य, इच्छाशक्ति, अदम्य भावावेग और बुद्धिमत्ता में नीहित है। मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करने ... और सर्वहारा जनवाद की सच्ची समझदारी को विस्तारित करने के लिए सोवियत यूनियन को कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयतावाद तक ले जाकर जैसा कि स्टालिन ने किया इसमें रूस और दुनिया के लोगों के इतिहास में क्लासिकल युग का एक नया अध्याय जोड़ दिया है।” (मास्को डायरी) एक अन्य प्रसिद्ध मानवतावादी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, “स्टालिन अद्वितीय तजुबों के धनी राजनीतिज्ञ थे उन पश्चिमी ताकतों के शासकों के मुकाबले जो एक स्वतःप्रवृत्त और बुरी व्यवस्था से चिपके हुए हैं जिसमें खोखले जुमले, मनगढ़ंत इतिहास और पुगने नित्यकर्म हैं ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे भग्न मौम कलाकृतियों में जीर्ण चित्रों की कटावें हों। (जीवीशा, एच पियर्सन—ए पोस्ट स्क्रिप्ट कोलिनीस, 1951) नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने निम्न शब्दों में स्टालिन के प्रति अपनी श्रद्धा जताई थी, “युद्धोपरांत यूरोप में सिर्फ एक ताकत है जिसके पास एक योजना है जो परीक्षणयोग्य है और वह ताकत सोवियत यूनियन है। आज यदि यूरोप में कोई एक व्यक्ति है जिसके हाथ में अगले कुछ दशकों के लिए यूरोपियन राष्ट्रों का भविष्य है तो वह व्यक्ति मार्शल स्टालिन है।” (सिंगापुर से रेडिया भाषण, शंकरीप्रसाद बसु द्वारा ‘सुभाष चन्द्र एण्ड नेशनल प्लानिंग’ में उद्धृत) जब युद्ध अपने पूरे उफान पर था रवीन्द्रनाथ तब वस्तुतः मृत्युशय्या पर थे उन्होंने पूछा था— “मुझे रूस का समाचार बताओ।” जब बताया गया कि शायद लाल फौज जर्मन आक्रमण को पीछे धकेलने में सक्षम होंगी, तो उनका चेहरा चमक उठा और उन्होंने कहा, “ऐसा होना ही निश्चित था, सिर्फ वही यह कर सकते हैं और वे सफल होंगे।” (कविकथा—प्रशांत चन्द्र महोलानोबिशा, विश्व भारती पत्रिका, 1350 बंगाली वर्ष) युद्ध के दौरान मास्को में अमेरिकी राजदूत एवरेल हैरीमैन ने कहा था, “युद्ध नेता स्टालिन लोकप्रिय थे और इसमें संदेह नहीं कि वही एक थे जिन्होंने सोवियत यूनियन को एकजुट रखा। मैं नहीं समझता कि अन्य कोई ऐसा कर सकता था। एक आपातकाल में राष्ट्रीय नेता स्टालिन के लिए अपनी अगाध प्रशंसा पर मैं जोर देना चाहूँ—ऐतिहासिक अवसरों में से एक जब एक व्यक्ति ऐसा एक तफका ला सका। बारीकियों को पकड़ने और उन बारीकियों पर काम करने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। पूरी वार मशीन की जरूरतों के प्रति वे बहुत चौकस थे। ये एक अफसरशाह के चारित्रिक लक्षण नहीं बल्कि एक निहायत सक्षम और जोशीले युद्ध नेता के लक्षण थे।” भूतपूर्व अमेरिकन राजदूत जोसेफ डेविस ने अपनी पुस्तक “मिशन टू मास्को” में लिखा: “बहुतों ने मुझे से पूछा जब हिटलर रूस में दाखिल हुआ तो उसे देशद्रोही क्यों नहीं मिले? मैंने जो कहा वह है कि बहुत पहले ही स्टालिन ने उन्हें चिन्हित कर लिया था और उखाड़ फेंका था। खुली अदालत में मुकदमा चलाने के बाद इन देशद्रोहियों को खिलाफ स्टालिन ने दण्डात्मक कार्रवाई की थी और वह भी अमेरिकी राजदूत सहित विभिन्न देशों के प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में।” जब पूरी दुनिया ने उन्हें फिर आखों पर बिठाया था, दुनिया भर के कम्युनिस्टों ने उन्हें अपना शिक्षक माना था, गैर-कम्युनिस्ट जनवादपसंद मानवतावादियों ने युग के हीरो के रूप में उनकी प्रशंसा की थी तब भी उन्होंने अपने बारे में कहा, “मैं लैनिन का एक अनुयायी हूँ, उनका योग्य अनुयायी होना ही मेरी इच्छा है।” उनके अनुसार यही उनकी असली पहचान थी। संशोधनवादी खुर्रचेव ने आरोप लगाया कि स्टालिन ने दूसरे विश्वयुद्ध में लाल फौज की जीत का श्रेय खुद हड़पने का प्रयास किया था। लेकिन वास्तविकता ठीक इसके उलट थी। युद्ध के बाद, जब सभी ने यह निश्चित मान लिया था कि विजय परेड में स्टालिन सलामी लेंगे, स्टालिन ने मार्शल जुकोव को सलामी लेने के लिए कहा। अपने विजय भाषण में स्टालिन ने कहा, “सर्वप्रथम हमारी विजय का मायने है कि हमारी सोवियत सामाजिक व्यवस्था की विजय हुई, कि सोवियत सामाजिक व्यवस्था सफलतापूर्वक युद्ध की अग्नि परीक्षा में सफल हुई और इसमें संदेहातीत रूप से अपनी जीवंतता को सिद्ध किया... युद्ध की प्रगति के दौरान हमारी मातृभूमि प्रथम दर्जे की नियमित सेना हासिल कर सकी जो हमारे लोगों की महान समाजवादी उपलब्धियों को बरकरार रख सकी और सोवियत यूनियन के राजकीय हितों की रक्षा कर सकी। इस तथ्य के बावजूद कि चार वर्षों से सोवियत यूनियन अभूतपूर्व पैमाने पर विशाल खर्चों की मांग पूरा करने के लिए युद्ध छेड़े हुए था, हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था ताकतवर हो रही है।... यह सब मजदूरों और सामूहिक फार्मों के किसानों का, सोवियत बुद्धिजीवियों का, हमारे देश की महिलाओं और नौजवानों के बहादुराना प्रयासों का परिणाम है जो महान बॉलशेविक पार्टी द्वारा प्रेरित और संचालित हुए थे।”

फासीवादी सैन्य शक्ति पर लाल फौज की फतह ने दुनिया भर में मुक्ति संघर्षों की बाढ़ ला दी

यह फासीवाद पर नहीं बल्कि फासिस्ट सैन्य शक्ति पर शानदार ऐतिहासिक विजय है। इस तरह स्टालिन, लाल फौज और बहादुर सोवियत जनता ने पैशाचिक फासिस्ट ताकतों द्वारा पूरी दुनिया को पैरों तले रेंदें जाने से बचाया। शिकारी फासिस्ट भेड़ियों के जबड़ों से इस वांछित जीत को हासिल करने के लिए 26 लाख सोवियत लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मृतकों में लाल फौज के बहादुर सिपाही, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अगुआ नेता-कार्यकर्ता, गुरिल्ला गुप्तों के सदस्य और आम सोवियत नागरिक शामिल थे जो समाजवाद और पूरी दुनिया को बचाने के लिए कटिबद्ध थे। किसी अन्य देश ने मानव जीवन और सम्पत्ति का इतने भारी पैमाने का नुकसान नहीं सहा जितना की सोवियत यूनियन को सहना पड़ा। आज अमेरिकी साम्राज्यवादी जीत हासिल करने की डींग हांक रहे हैं। अमेरिकी सिने कम्पनियों उसका दर्शन के लिए फिल्में बना रही हैं। लेकिन सच्चाई का इससे दूर का भी वास्ता नहीं है। पर्ल हार्बर पर बमबारी के सिवाय अमेरिका ने युद्ध में वस्तुतः कोई भी नुकसान नहीं सहा। बल्कि युद्ध के बाद विश्व बाजार पर कब्जा जमाने के लिए अमेरिका सबसे बड़ा दावेदार बन कर उभरा मसलन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान युद्ध में तबाह हो गए थे और यह उनके ध्वंसावशेषों पर पनपा। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की जीत ने साम्यवाद की प्रतिष्ठा बढ़ा

दी थी और विश्व क्रान्ति को तेज करने के लिए दुनिया भर में मजदूर वर्ग को प्रेरित कर दिया था। उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिला था। बर्लिन की तरफ लाल फौज के विजय अभियान के दौरान अधिकतर पूर्वी यूरोपीय देशों में समाजवाद स्थापित हो गया था। महान माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रान्ति की फतह अवश्यभावी हो गई थी। विश्व साम्यवादी आन्दोलन ने जबर्दस्त गति पकड़ ली थी। हर दिल में स्टालिन के नाम की छाप थी। जिन्होंने स्टालिन को बदनाम करने का प्रयास किया वे इतिहास में खुद ही बदनाम हो जाएंगे जबकि स्टालिन पर कोई आंच नहीं आएगी और एक महान चरित्र, एक महान कम्युनिस्ट नेता के रूप में वे हमारे दिलों में बने रहेंगे।

संशोधनवादी षडयंत्र और स्टालिन को बदनाम करने ने साम्यवाद की अग्रगति को रोक दिया

लेकिन बाद में इतिहास ने एक भिन्न मोड़ ले लिया। 1953 में स्टालिन के देहांत के बाद खुर्रचेववादी आधुनिक संशोधनवादियों ने सोवियत यूनियन में सत्ता हथिया ली। विश्व साम्राज्यवाद-पूँजीवाद द्वारा सहायता और प्रोत्साहन पा कर उन्होंने समाजवाद के स्तम्भों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और प्रतिक्रान्ति की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अंततः 1990 के दशक की शुरुआत में प्रतिक्रान्तिकारी उत्थान के माध्यम से सोवियत समाजवाद ध्वस्त कर दिया गया। इसे हासिल करने में संशोधनवादी गुट ने स्टालिन के खिलाफ निन्दा अभियान छेड़ दिया और उनकी अंधोरिटी को तुच्छ करने का प्रयास किया। उस समय एस.यू.सी.आई.(सी) के संस्थापक महासचिव और अन्यतम मार्क्सवादी चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष की एकमात्र आवाज थी जिन्होंने दुनिया को, विशेषकर कम्युनिस्टों को इसमें अंतर्निहित खतरे के प्रति आगाह किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि “स्टालिन को मिटा देने का अर्थ है इस अंधोरिटी को ही नकार देना और इसलिए लेनिनवाद की उनकी व्याख्या को ही टुकरा देना जो कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद की आज के दिनों की समझ है। ऐसा करने से ट्रांटस्कीवादियों और बुखारिनपथियों के खिलाफ निरन्तर संघर्ष चला कर मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी प्राणसत्ता को स्टालिन ने जिस तरह रक्षा की थी, उनके इस अनुपम संघर्ष का इतिहास भावी पीढ़ियों के लिए अंधकारमय और अज्ञात ही रह जाएगा और वे पीढ़ियों मार्क्सवाद-लेनिनवाद के बारे में वैचारिक तौर पर फौलादी समझ से लैस होने के अवसर से वंचित रह जाएंगी। इसका मतलब हो जाएगा हर तरह के प्रतिक्रान्तिकारी विचारों को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के नाम पर चलने का न्यौता दे देना और साम्यवादी आन्दोलन को सैद्धान्तिक बुनियाद को धक्का पहुँचा देना। संक्षेप में, यह वस्तुगत रूप से स्वयं लेनिन को ही बेताज कर देगा।” (चुनिन्दा रचनाएँ खण्ड 1 पृष्ठ 84) यह एक स्वागतयोग्य संकेत है कि रूस के साथ-साथ दुनिया के अन्य बहुत से हिस्सों, विशेषकर पूर्वी यूरोप के पूर्ववर्ती समाजवादी राज्यों के लोग लेनिन-स्टालिन के चित्र लेकर पुनः उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति सम्पन्न करके समाजवाद को फिर बहाल करने के लिए जो जरूरी है वह है सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के तहत एक सचेत संगठित आन्दोलन को विकसित और तीव्रतर करनी। साथ ही साथ हमें यह सबक भी याद रखना जरूरी है कि हिटलर-मुसोलनी-तोर्जो धुरी की युद्ध प्रणय के साथ फासीवाद का खान्सा नहीं हो गया है। फासीवाद सिर्फ नग्न मिलिट्री तानाशाही ही नहीं होती है बल्कि जैसा कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद की कसौटी पर कॉमरेड शिवदास घोष ने दिखाया है कि यह “एक ऐतिहासिक तौर से अनुकूलित प्रतिक्रान्ति का स्वरूप है जिसमें अग्रिम कदम उठा कर पूँजीवाद क्रान्ति को दूर हटाना चाहता है। इसे मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ लोगों के बढ़ते असंतोष के चलते संकटग्रस्त, अस्त-व्यस्तता के लिए बदनाम पूँजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है।” (संकलित रचनाएँ खंड 1 पृ. 55) उन्होंने व्याख्या की थी कि हासो-नुख मरणासन्न संकट-ग्रस्त पूँजीवाद की मौजूदा अवस्था में, कैसे फासीवाद तमाम पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देशों की चारित्रिक विशेषता बन गया है चाहे वे विकसित हो या पिछड़े। चेतावनी देते हुए उन्होंने परिभाषित किया कि फासीवाद किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, यहाँ तक कि संसदीय जनतंत्र का मुखौटा बरकरार रखते हुए भी “दर्शन और संस्कृति के क्षेत्रों में फासीवादी आधुनिक विज्ञान के साथ भाववाद का विचित्र समिश्रण है।” (संकलित रचनाएँ खंड 4 पृ. 14) उन्होंने विस्तारित व्याख्या दी कि एक तरफ पूँजीपति वर्ग फासिस्ट स्टेट की आर्थिक और मिलिट्री ताकत को विकसित करने के अपने प्रयास में विज्ञान के तकनीकी पहलुओं को अख्तियार करता है और दूसरी तरफ तमाम बुराइयों की जो शोषणमूलक पूँजीवादी व्यवस्था की सहजात बुराईयें हैं कि रामबाण औषधि के रूप में तमाम तरह के विज्ञान-विरोधी धार्मिक सनकों तथा तमाम तरह के आदर्शवादी और भाववादी तिकड़मों को परसता रहता है और आज राष्ट्रीय संस्कृति और विरासत के नाम पर भी इन्हें पेश करता है। भारत में उपजा परिदृश्य इसकी मुँह बोलती मिसाल है।

क्रान्ति को दूर रखने के फासीवादी षडयंत्र को नाकाम करें

इसलिए दूसरे विश्व युद्ध में फासीवाद पर विजय की 70वीं वर्षगांठ मनाते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हालाँकि जर्मनी-इटली-जापान के फासीवादी गठजोड़ को सामरिक तौर पर परास्त कर दिया गया था लेकिन फासीवाद के खिलाफ संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा बहुत पहले इंगित किया गया था, फासीवाद के विशिष्ट लक्षण हैं आर्थिक केन्द्रीयकरण, पूँजीवादी-साम्राज्यवादियों के हाथों में राजनीतिक सत्ता का अधिकतम केन्द्रीयकरण, प्रशासन में अटल कठोरता, सांस्कृतिक रेजिमेण्टेशन और एकाधिकारी पूँजीपतियों के स्वार्थ के साथ राजसत्ता का एकीकरण और इस तरह राजसत्ता को उनका ताबेदार बना देना, तमाम पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में ये लक्षण विभिन्न आयामों में दृष्टिगोचर हैं। आज जब तमाम पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में और भी स्पष्टता से फासीवाद अपना मनहूस सर उठा रहा है तब मार्क्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओ त्से-तुंग-शिवदास घोष की अमूल्य सीखों पर आधारित गहन वैचारिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक संघर्ष फासीवादी के खिलाफ छेड़ना और भी लाजमी हो गया है ताकि आर्थिक दमन और वित्तीय बर्बरता को तीव्रतर करने, संघर्षों से अर्जित उत्पीड़ित लोगों के तमाम जनवादी अधिकारों को छीन लेने, विरोध की आवाज को कुचलने और विशेष तौर पर ताकिक चिन्तन को भोथरा कर देने, कार्य-कारण के वास्तविक रास्ते से बदल कर मानसिक प्रक्रिया को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की मिथकीय अंधी गली में धकेल देने, नीति-नैतिकता और संस्कृति के आधार को ध्वस्त कर देने और इस प्रकार लोगों के क्रान्तिकारी अभ्युत्थान को परे धकेल देने की साम्राज्यवादियों पूँजीवादियों के षडयंत्र को नाकाम किया जा सके।

जनजीवन की ज्वलंत मांगों को लेकर प्रदर्शन



दिल्ली : बुराड़ी सर्वोदय बाल/बालिका विद्यालय का जर्जर भवन दोबारा बनाये जाने, परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने, हर सुविधायुक्त हस्पताल बनाने, इलाके में साफ-सफाई की व्यवस्था करने और कालोनियों को नियमित करने की मांगों पर 20 मई को एसयूसीआई (सी) की उत्तर पश्चिम इकाई द्वारा एक प्रदर्शन किया गया। इसमें बुराड़ी, बलवा व जहांगीरपुरी के लोगों और भवन निर्माण मजदूरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इन कालोनियों की समस्याओं सम्बन्धी 8 सूत्री और भवन निर्माण कारीगर-मजदूरों की 16 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला इकाई के सचिव डॉ. मैनेजर चौरसिया ने कहा कि आन्दोलन के जरिये ही इन समस्याओं का समाधान सम्भव है। प्रदर्शन की अगुआई डॉ. राकेश ने की।

सभा का संचालन डॉ. निर्मल कुमार ने किया। सभा को डॉ. प्रेमपाल, प्रियंका, मौसम, अमरजीत ने भी सम्बोधित किया।

साम्यदायिक तनाव व दहशत फैलाने के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो

रोहतक : 29 मई को जारी एक बयान में एसयूसीआई (सी) के हरियाणा राज्य सचिव डॉ. सत्यवान ने फरीदाबाद के अटाली गांव के अल्पसंख्यक समुदाय के पीड़ित परिवारों को पूर्ण सुरक्षा देने, उनके नुकसान की पूरी भरपाई कर उन्हें पुनः बसाने, जान-माल के नुकसान के खोफ और धूप, गर्मी, भूख-प्यास से पीड़ित लोगों को न्याय दिया जाने और उनमें भाईचारा, आपसी सद्भाव और विश्वास बहाल किया जाने, इस धिनौनी घटना में आगजनी, मारपीट व दहशत फैलाने के दोषियों के खिलाफ कड़ी व कारगर कार्रवाई करने, इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाने जिसमें पुलिस-प्रशासन की मिलीभगत और भाजपा सरकार के नकारात्मक, लापरवाह व तमाशबीन बने रहने के रवैये को जांच का विषय बनाने की मांग की। डॉ. सत्यवान ने बहुसंख्यक समुदाय के समझदार और नेकचिह्न वाले लोगों से आगे आने, हालत को सामान्य बनाने और आपसी भरोसे व भाईचारे को बहाल करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी धिनौनी घटनाएँ पूरे समाज के लिए घातक हैं। इनकी पुनरावर्ती न हो, इसके लिए खट्टर सरकार को ठोस व कारगर कदम उठाने चाहिए।

“फासीवाद का खतरा और उसका समाधान किस रास्ते” विषयक विचार-गोष्ठी आयोजित

रांची (झारखण्ड) : द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की करारी हार हुई। फासीवाद पर समाजवाद की ऐतिहासिक जीत हुई। इसकी 70वीं सालगिरह के मौके पर 12 मई को रांची के पुरलिया रोड स्थित विकास मैत्री भवन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की तरफ से एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसका विषय था “फासीवाद का खतरा और उसका समाधान किस रास्ते”। इसमें विभिन्न वामदलों के नेतागण ने अपने विचार रखे।

दलित महिलाओं के उत्पीड़न पर रोष प्रकट

इलाहाबाद : शाहजहांपुर में पांच दलित महिलाओं को मारपीट कर निर्बन्ध कर घुमाये जाने की घटना के विरोध में 20 मई को एआईएमएसएस की इलाहाबाद इकाई ने मानवता को शर्मशार करने वाली इस घटना की भर्त्सना की और अपना शोध व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कराने, फास्ट ट्रेक कोर्ट के माध्यम से त्वरित न्याय देने और अपराधियों को कड़ी सजा देने की अपील की। ज्ञानशीला शर्मा, कल्याणी रायचौधरी, गीता त्रिपाठी, सुधा त्रिपाठी, रश्मि मालवीय, राजेश्वरी, संध्या, रेनु, राजलक्ष्मी आदि ने बात रखी। संचालन रश्मि मालवीय ने किया।

हड़ताल/बंद सम्बन्धी खबर के प्रकाशन पर पाबंदी के फैसले बारे एआईयूटीयूसी का बयान

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हड़ताल/स्ट्राइक/बंद सम्बन्धी खबर के प्रकाशन/वितरण के बारे में शिलांग के माननीय हाई कोर्ट द्वारा 27 मई 2015 को दिये गये फैसले पर ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेण्टर (एआईयूटीयूसी) के महासचिव डॉ. शंकर साहा ने 29 मई, 2015 को निम्न बयान जारी किया :

“यह गहरी चिंता का विषय है कि हाल ही में शिलांग के माननीय हाई कोर्ट ने हड़ताल/स्ट्राइक/बंद सम्बन्धी किसी भी खबर के प्रकाशन/वितरण पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने मीडिया द्वारा ऐसी खबर छापने या वितरित किये जाने पर अदालत की मानहानि के आरोप

में मीडिया के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने की भी धमकी दी है।

हमारे विचार से यह फैसला देश के न्यायोचित जनवादी आन्दोलन के लिए न केवल खतरे का संकेत देने वाला है बल्कि अस्वीकार्य भी है।

बड़े कष्टों से अर्जित जनवादी अधिकारों के बचाव में एकजुट होकर उठ खड़े होने और इनकी रक्षा करने के लिए आगे आने का हम सभी जनवादी ख्यालाल वाले और नेक विचारों वाले लोगों और साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और ट्रेड यूनियन संगठनों से आग्रह करते हैं।

आईआईटी मद्रास के अम्बेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल पर लागये बैन की एआईडीएसओ ने की कड़ी निन्दा

आईआईटी मद्रास के अम्बेडकर स्टडी सर्कल पर लागये बैन की कड़ी निन्दा करते हुए एआईडीएसओ के महासचिव डॉ. अशोक मिश्रा ने 30 मई को जारी एक बयान में कहा :

यह साफ जाहिर है कि सरकार के खिलाफ किसी तरह की आलोचना को मोदी सरकार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। देश में मुक्त, बेबाक सामाजिक-राजनैतिक बहस और चर्चा की गुंजाइश को नकारा जा रहा है जिस इस सरकार के फासीवादी चरित्र का संकेत है। जब केन्द्र सरकार के मानव संशाधन विकास मंत्रालय ने सामाजिक-साजनैतिक बहस छेड़ने पर आईआईटी मद्रास के एक स्वतंत्र छात्र संस्था अम्बेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल पर बैन लगाने का फरमान जारी किया तो यह एक बार फिर उजागर हो गया। नरेन्द्र मोदी के खिलाफ

‘नफरत’ फैलाने के बहाने पहले भी आईआईटी मद्रास ने एक चर्चा के मंच पर बैन लगाया था क्योंकि इसने हिन्दी के इस्तेमाल, गौहत्या, घर वापसी कार्यक्रम और वेदों को बढ़ावा देने पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाये थे। इस प्रकार मोदी सरकार ने बोलने की आजादी के लिए कोई स्थान होने से मना किया और देश के सभी नागरिकों के बोलने के अधिकार का हनन किया। मोदीजी, केन्द्र व बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें और बीजेपी-आरएसएस-संघ परिवार के नेतागण अब तय किया करेंगे कि लोग क्या खायें और क्या बोलें। यह जनतंत्र की हत्या के सिवा और कुछ नहीं है। हम बोलने की आजादी पर इस हमले का पुरजोर विरोध करते हैं और आम लोगों, खासकर छात्रों से इसके प्रतिवाद में अपनी आवाज बुलंद करने की अपील करते हैं।

पटना में ‘अपसंस्कृति का दुष्प्रभाव और

ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में 24 मई को पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सेमिनार हॉल में “अपसंस्कृति का दुष्प्रभाव और महिलाएँ” विषयक सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार की शुरुआत संगठन की पटना जिला संयोजिका डॉ. अनामिका ने की और अध्यक्षता राज्य सचिव डॉ. साधना मिश्रा ने की।

सेमिनार को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य डॉ. अरूण कुमार सिंह ने कहा कि इस वर्ग-विभाजित पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा शोषण की शिकार महिलाएँ हैं। वे दोहरे शोषण, पूंजीवादी शोषण और पुरुषप्रधान समाज के शोषण की शिकार हैं। उन्होंने कहा कि आज शासक पूंजीपति वर्ग पत्र-पत्रिकाओं, फिल्मों, धारावाहिकों व गीत-संगीत के माध्यम से महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में परोस रहा है। साथ ही नौजवान पीढ़ी को उपभोक्तावादी संस्कृति के

महिलाएँ” विषयक सेमिनार आयोजित

दलदल में धकेलकर हैवान बनाने की भरसक कोशिश हो रही है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा की मार भी महिलाओं को ही ज्यादा झेलनी पड़ रही है। उन्होंने इस दोहरे शोषण से मुक्ति के लिए उच्च नीति-नैतिकता पर आधारित जोरदार महिला आंदोलन गठित करना वक्त की मांग बताया और महिला आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन की चल रही लड़ाई के परिपूरक बनाने पर बल दिया।

प्रो. भारती एस कुमार ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें एक तरफ, शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर रही हैं; तो दूसरी तरफ, शराबखोरी, नशाखोरी, अश्लीलता, नग्नता इत्यादि को समाज में परोसा जा रहा है, जिससे लोगों, खासकर युवक-युवतियों में नीति-नैतिकता और मूल्यों में भारी गिरावट आ रही है। उनमें सामाजिक सरोकारों के प्रति उदासीनता बढ़ रही है।

सेमिनार को सुक्ति सेनगुप्ता, मालविका राय, रेखा, वंदना तथा इन्दु ने भी संबोधित किया।

मिड डे मील कार्य निजी एजेंसियों को सौंपने का विरोध

भिवानी : अपनी माँगों पर 26 मई को यहाँ ऑल इण्डिया यूटीयूसी से सम्बन्धित मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन के बैनर तले मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त जिला भिवानी की मार्फत मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

मिड डे मील कार्य को प्राइवेट कम्पनी को न देने, 15000 रुपये न्यूनतम वेतन देने, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, हाजिरी रजिस्टर लगाने, छुट्टियों के पैसे न काटने, भविष्य निधि, पेंशन, जीवन बीमा आदि सामाजिक सुरक्षा देने, साल में कम से कम दो वर्दियाँ देने, बीमार पड़ने पर सवेतन अवकाश और मृत्यु या दुर्घटना होने मुआवजा देने, रसोई घर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध और गैस सिलेण्डरों व अन्य जरूरी सामानों का प्रबंध करने, मिड डे मील काम को देखने व प्रबंध करने के लिए अलग से स्टाफ भर्ती



करने की मांग ज्ञापन में की गई।

लघु सचिवालय गेट पर पहुंचकर जुलूस सभा में बदल गया। सभा को संयुक्त कर्मचारी मंच के सुबे सिंह, ऑल इण्डिया यूटीयूसी के राज्य कमेटी सदस्य रामफल, जिला कमेटी सदस्य राजकुमार, धर्मवीर और मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की नेत्री राजबाला व मीरा ने सम्बोधित किया।

“Print-line